International Journal of Scientific Research in Science and Technology
Print ISSN: 2395-6011 | Online ISSN: 2395-602X (www.ijsrst.com)
doi : https://doi.org/10.32628/IJSRST

आजमगढ़ जनपद जनसंख्या एंव कृषि विकास का प्रतिरूप – एक भौगौलिक अध्ययन

[1]अलका राय, [2]शिवलोचन सिंह
भूगोल विभाग, राष्ट्रीय पी० जी० कालेज जमुहाई, जौनपुर

Article Info
Volume 8, Issue 2
Page Number : 699-708

Publication Issue
March-April-2021

Article History
Accepted : 05 April 2021
Published : 20 April 2021

सारांशः–ऐतिहासिक रूप से, भूमि के मुद्दे और जाति व्यवस्था पारंपरिक ग्रामीण भारत में आपस में जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश में जाति और सामुदायिक राजनीति की वृद्धि और मुखरता आर्थिक विकास को पर्याप्त और समान रूप से बढ़ावा देने में विफलता और शासन और नीति प्रक्रियाओं के केंद्रीकृत ढांचे की कमजोरी का परिणाम थी। आजमगढ़ जिले में भी, कृषि संबंधों की प्रकृति अतीत से उच्च और निचली जातियों के बीच असमान है। स्वतंत्रता के बाद, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया और विभिन्न राज्य पहलों ने समाज के सीमांत वर्ग की स्थिति में सुधार किया है और आजमगढ़ जिले में भूमि और जाति के संबंध में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। यह लेख आजमगढ़ जिले की निचली जाति (एससी) पर भूमि सुधारों और अन्य राज्य पहलों के प्रभाव पर चर्चा करता है। निष्कर्ष निचली जाति की बदलती स्थिति और विभिन्न राज्य पहलों से बदलते कृषि संबंधों को दर्शाते हैं।

शीर्षक :– विकास, राज्य की पहल, कृषि संबंध, निचली जातियां, आजमगढ़।

परिचय

भारतीय राजनीतिक प्रक्रिया की विशिष्टता इस तथ्य में निहित है कि भारतीय राज्य की वैधता को चुनौती देने वाले हित समूहों, जाति गतिशीलता, राष्ट्र–निर्माण, लोकतंत्रीकरण और उपनिवेशवाद के बीच निरंतर संपर्क रहा है और श्लोक कल्याणश, श्विकासश के बुनियादी सिद्धांतों का मार्गदर्शन करता रहा है। , सामाजिक न्याय और श्राष्ट्रीय हितश। इन गतिशील कारकों ने राज्य और समाज के बीच संबंधों की प्रकृति और सामग्री को आकार दिया था और समय के साथ महत्वपूर्ण परिणाम सामने आए थे, जिसमें शामिल थे, जाति गठबंधन के उदय के माध्यम से उच्च जाति के आधिपत्य का पतन, विकेंद्रीकरण पर प्रोत्साहन, कुलीन राजनीति का आवधिक पतन और उदारवाद का उदय। विकास रणनीति को विकास रणनीति में बदलने के साथ–साथ अर्थशास्त्र; सशक्तिकरण, राज्य के हस्तक्षेप, निम्नवर्गीय आंदोलनों और अन्य जातीय आंदोलनों का उदय; और अंत में, राजनीतिक व्यवस्था की संचालन इकाई के रूप में श्राष्ट्रश के बजाय क्षेत्रीय मुद्दों का उदय।

गरीबी और राजनीति के बीच मौन संबंधों के विभिन्न चरण रहे हैं जो स्वतंत्रता के बाद के युग के दौरान विभिन्न चरणों में भारतीय राज्य के आदर्शों और मार्गदर्शक सिद्धांतों के लिए एजेंडा निर्धारित करते हैं। पहला चरण श्संवैधानिक प्रक्रियाश था जो प्रकृति में राष्ट्रवादी था और भारतीय संविधान के निर्माण के अलावा सामुदायिक विकास और श्उपनिवेशवादश के शुरुआती प्रयासों में परिलक्षित होता था। दूसरे चरण को विकास चरण कहा जा सकता है, जिसने ग्रामीण गरीबों के क्षमता निर्माण पर जोर दिया और 1950 के दशक के भूमि सुधारों की शुरुआत की, जो अंततः अनुपयुक्त साबित हुए क्योंकि यह भूमिहीन मजदूरों को अपनी अवधारणा में शामिल करने में विफल रहा। ग्रामीण बिजली संरचना को फिर से आकार देना। 1960 के दशक के राष्ट्रव्यापी ग्रामीण आंदोलनों ने तीसरे चरण का निर्माण किया जब

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

नव सशक्त किसानों ने अपने रोजगार की स्थिति, मजदूरी, गरिमा और न्याय में सुधार के लिए प्रणाली पर दबाव डाला, जिससे राज्य को व्यापक योजनाओं के साथ जवाब देना पड़ा जिससे श्हरित क्रांतिश हुई। गरीबी और राजनीति के बीच संबंधों का चौथा और सबसे महत्वपूर्ण चरण 1980 के दशक से शुरू हुआ और यह राज्य–केंद्रित कल्याणकारी राज्य के बाजार उन्मुख अर्थव्यवस्था के संक्रमण में परिलक्षित हुआ, जिसे लोकप्रिय रूप से ष्उदारीकरण का युगष् कहा जाता था।

यदि हम भारतीय परिदृश्य को समझने के लिए इस ढांचे को अनुकूलित करते हैं, विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, तो यह सुझाव देता है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत क्षेत्रीय असमानताओं का निर्माण और विस्तार किया गया था। दादाभाई नौरोजी के अग्रणी कार्यों ने एक व्यापक और व्यवस्थित विवरण प्रदान किया कि कैसे भारत से स्थानीय संसाधनों को बाहर निकालने के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया, जिससे अभाव और गरीबी का एक दुष्चक्र पैदा हुआ। जो क्षेत्र कभी कुशल उत्पादन के साथ संपन्न थे, वे व्यवस्थित रूप से अपने कौशल से वंचित थे और तैयार माल के उत्पादकों से कच्चे माल के उत्पादकों और तैयार माल के बाजार में बदल गए। दत्त (1940) ने आगे औपनिवेशिक शोषण की इस घटना का वर्णन किया और बताया कि कैसे इसने क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर असमानताएं पैदा की हैं, जिन्होंने असमानताओं और असमानताओं को कम करने के लक्ष्य वाली विकास नीतियों की चिंताओं में केंद्रीय चरण ग्रहण किया है। हालांकि, कई हालिया अध्ययनों से संकेत मिलता है कि ये नीतियां और रणनीतियां अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकीं और राज्यों और क्षेत्रों के बीच किसी भी अभिसरण के बहुत कम सबूत हैं, खासकर सुधार के बाद की अवधि के बाद। नूरबख्श (2003) ने विचलन की ओर सुझाव दिया जो अभिसरण के बजाय विभिन्न क्षेत्रों के बीच हो रहा है। कई अन्य अध्ययनों (द्रेज और सेन, 1995) ने उल्लेख किया है कि भारत में विभिन्न राज्यों/क्षेत्रों के बीच आर्थिक और सामाजिक विकास में उल्लेखनीय विविधता रही है। दत्त और रैवेलियन, 1998 द्वारा यह नोट किया गया था कि जो राज्य भौतिक बुनियादी ढांचे और मानव संसाधनों के विकास में ईमानदार थे, उन्होंने गरीबी कम करने में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। एक अन्य अध्ययन में, दत्त और रैवेलियन (2002) ने पाया है कि राज्य में साक्षरता दर में अंतर ने गरीबी कम करने में सफलता को परिभाषित करने में प्रमुख भूमिका निभाई है। यह इस पृष्ठभूमि में है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की निचली जातियों (एससी) पर ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के प्रभाव को समझा जा सकता है, हालांकि, इस चेतावनी के साथ कि इन कार्यक्रमों का निर्माण और कार्यान्वयन क्षेत्रीय जरूरतों की कमी के कारण प्रकृति में केंद्रीय थे। मुख्य उद्देश्य पूर्वी उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ जिले में निचली जाति की स्थिति पर प्रकाश डालता है। यह विभिन्न राज्य विकास पहलों से बदलते कृषि संबंधों का पता लगाने का भी प्रयास करेगा।

यूपी के विशेष संदर्भ में भारत में निचली जाति का परिदृश्य

जाति सामाजिक–सांस्कृतिक घटना है जो केवल भारत में मौजूद है। जाति की कुछ विशिष्ट विशेषताएं हैं जो हिंदू दर्शन में दिए गए निर्देश के आधार पर कई अलग–अलग अंगूरों को नियमित करती हैं (अम्बेडकर; 1936, 1945)। यह भी एक तथ्य है कि उत्तर भारतीय मैदानों में जाति व्यवस्था, जहां आर्यों और उनकी संस्कृति संस्कृति ने सबसे गहरा प्रभाव डाला था, दक्षिण में उससे मौलिक रूप से भिन्न है। दक्षिण में, ब्राह्मण संख्या में कम होते हुए भी द्विज जातियों के एकमात्र प्रतिनिधि हैं। दक्षिण में उत्तर भारतीय राजपूतों और वैश्यों का कोई प्रतिरूप नहीं है। परिणामस्वरूप, दक्षिण में ब्राह्मणों की प्रवृत्ति शेष शूद्र आबादी से अधिक अलग हो गई है। लेकिन इसके विपरीत, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का अपेक्षाकृत बड़ा हिस्सा द्विज जातियों से बना है। इसलिए, उत्तर में ब्राह्मणवाद अपेक्षाकृत कम अत्याचारी रहा है। उत्तर प्रदेश में विभिन्न जातियों के कर्मकांडों में अधिक निरंतरता है, जिसके कारण सामाजिक स्थिति और राजनीतिक सत्ता का सामान्य बंटवारा हुआ है। ब्राह्मणों के साथ–साथ अन्य द्विज जातियों की भी आधुनिक पेशे और सत्ता संरचना तक पहुंच है। यह सबसे प्रमुख कारणों में से एक रहा है कि राज्य में निचली जाति के शूद्रों या उन्नत अछूत जातियों की कोई बड़ी लामबंदी नहीं हुई थी जो कि दक्षिणी राज्यों और महाराष्ट्र में अतीत में हुई थी। इन राज्यों में खड़ी और असंतत पारंपरिक पदानुक्रमों की विशेषता वाला ब्राह्मणवाद, इन राज्यों में फला–फूला और बदले में, जातियों की राजनीतिक लामबंदी को बढ़ावा दिया है जो कि कर्मकांड–पदानुक्रम में अभी भी कम है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, दो बार जन्म लेने वाली जातियों के अपेक्षाकृत उच्च अनुपात वाले और अधिक क्रमिक और सन्निहित

सामाजिक बाधाओं वाले इन राज्यों में अवसर, स्थिति और राजनीतिक शक्ति की तलाश करने वाले अनुष्ठान से वंचित जातियों के नीचे से क्षैतिज लामबंदी की संभावना कम है (रुडोल्फ और रूडोल्फ, 1987,76–79)।

जाति व्यवस्था अपने सामाजिक पदानुक्रम के साथ और जाति समूहों के बीच धार्मिक, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक और न्यायिक संबंधों में स्थिति और रैंक की अंतर्निहित असमानता के साथ प्राचीन ऐतिहासिक काल से अस्तित्व में रही है। सबसे ऊपर पदानुक्रम में ब्राह्मण और अछूत हैं जो निचले सिरे पर आते हैं। हिंदू धर्म के हिस्से के रूप में अनुष्ठान शुद्धता और प्रदूषण जीवन के सभी क्षेत्रों में व्याप्त है। अधिकांश सांसारिक चीजों के साथ–साथ भोजन, कपड़ा और धातुओं में मूल्यों का एक क्रम या पदानुक्रम प्राप्त होता है, हमेशा उनकी उपयोगिता के आधार पर आवश्यक नहीं (पर्वथम्मा, 1981, 55) परंपरागत रूप से भारतीय समाज को सामाजिक बहिष्कार की विशेषता है और इसमें स्पष्ट असमानताएं संरचित हैं। कुछ सामाजिक असमानताएं और अक्षमताएं जाति की संस्था पर केंद्रित थीं, जो शीर्ष पर ब्राह्मणों और अनुसूचित जातियों या तथाकथित अछूतों के आधार पर स्थिति पदानुक्रम का गठन करती है। निम्न सामाजिक और धार्मिक स्थिति के कारण यह निम्नतम स्तर सामाजिक अन्याय और शोषण से पीड़ित था, जिसने इसे इसके लिए निर्धारित सामाजिक स्थिति से ऊपर उठने से रोक दिया। इस जाति के सदस्यों को सामान्य व्यवसायों में प्रवेश से वंचित कर दिया गया था, जो अपेक्षाकृत अच्छी तरह से भुगतान किए गए थे, ज्ञान का मार्ग बंद था और उन्हें व्यवसाय और शिक्षा तक कोई पहुंच नहीं थी। अनुसूचित जातियों (एससी) और महिलाओं की स्थिति लगभग समान थी और समाज की सामाजिक संरचना पर उनका प्रभाव पड़ता है। समाज की एक प्रथागत सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के रूप में जाति, पदानुक्रमित प्रकृति पर आधारित, समाज में विद्यमान सामाजिक तनाव का कारण है। दलित, जो भारत की कुल जनसंख्या का पाँचवाँ हिस्सा है, समाज के हर क्षेत्र में भेदभाव और बहिष्कार की सबसे गंभीर समस्या से पीड़ित है और उनमें सबसे नीचे जाति पदानुक्रम है। समाज में मौजूदा अस्पृश्यता, दलित को समाज में प्रमुख समुदाय के साथ लेन–देन से बाहर रखा (थोरात और ली, 2005)। पदानुक्रमित जाति संबंध हिंदू समाज की आधारशिला हैं। अनुसूचित जाति की प्रमुख समस्या अस्पृश्यता की सामाजिक भेदभावपूर्ण प्रथा और दयनीय आर्थिक स्थिति द्वारा अधिरोपित गरीबी है।

भारतीय समाज में, जाति एक पारंपरिक सामाजिक इकाई के साथ एक सुव्यवस्थित सामुदायिक जीवन का प्रतिनिधित्व करती है। ष्शुद्धष् ष्अशुद्धष् या मूल्यों और विचारों के एक समूह (ड्यूमॉन्ट, 1952; श्रीनिवास, 1962) की धारणा के आधार पर जाति का एक सरल अनुष्ठान पदानुक्रम है। समाजशास्त्रियों के बीच जाति पर चर्चा इसकी विशेषताओं पर केंद्रित है जैसे समाज का खंड विभाजन, सजातीय और वंशानुगत व्यवसाय आदि (घुर्ये, 1969)। जाति व्यवस्था अपने सामाजिक पदानुक्रम के साथ और जाति समूहों के बीच धार्मिक, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक न्यायिक संबंधों में स्थिति और रैंक की अंतर्निहित असमानता के साथ सबसे पहले ज्ञात ऐतिहासिक समय से अस्तित्व में है। पदानुक्रम के शीर्ष पर ब्राह्मण हैं, अछूत सबसे नीचे आते हैं और पारंपरिक व्यवस्था के तहत विभिन्न प्रकार की अक्षमताओं, अभावों और उत्पीड़न के अधीन थे।

उत्तर प्रदेश भारत के पांचवें सबसे बड़े राज्य का क्षेत्रफल 240928 वर्ग किमी है। और इसकी कुल जनसंख्या 19,95,81477, ग्रामीण जनसंख्या 15,51, 11022 और शहरी जनसंख्या 4,44,70,455 (जनगणनारू 2011) है। राज्य में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत जो दलित आबादी का एक बड़ा हिस्सा 21 प्रतिशत है। यदि यह एक अलग देश होता तो उत्तर प्रदेश केवल चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडोनेशिया को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का पांचवां सबसे अधिक आबादी वाला देश होता। 2001 की भारतीय जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की लगभग 80 प्रतिशत जनसंख्या हिंदू है, जबकि मुस्लिम जनसंख्या का लगभग 18.5 प्रतिशत है। शेष में सिख, बौद्ध, ईसाई और जैन शामिल हैं (जनगणना, 2001)।

इक्कीसवीं सदी की शुरुआत राज्य के प्रशासनिक ढांचे के कुछ पुनर्गठन के साथ हुई थी, जिसमें 18 राजस्व प्रभाग हैं, जिसकी अध्यक्षता 71 जिलों में फैले एक आयुक्त के नेतृत्व में होती है, जिनमें से प्रत्येक में एक कलेक्टर होता है। जिलों को आगे 312 तहसीलों (उप–मंडल) में बांटा गया है और विकास के उद्देश्य से ब्लॉकों (संख्या 915) में संगठित किया गया है। राज्य स्तर पर राजनीतिक गतिविधियों में लोगों की भागीदारी 403 सदस्यों की राज्य विधानसभा के निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से सुनिश्चित की जाती है और परिषद के दूसरे सदन में विधानसभा से अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं और कुछ प्रत्यक्ष जो विशेष रुचि समूहों जैसे स्नातक, शिक्षक, आदि का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुल गाँव 106774 हैं, जिनमें से 97184 बसे हुए गाँव हैं (भारत की जनगणना, 2011)। राज्य में जनजातीय समूहों

की नाममात्र उपस्थिति है, अनुसूचित जातियों का 21 प्रतिशत और जनगणना में अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) में एक गैर–गणना श्रेणी है, और इन तीन समूहों के लिए आरक्षण 50 प्रतिशत सीटों से अधिक नहीं हो सकता (चौहान, 2009)।

उत्तर प्रदेश की जाति संरचना उतनी कठोर और बहिष्करणवादी नहीं है जितनी दक्षिणी राज्य में इसके समकक्ष थे; तीखे विभाजन और मतभेदों के बजाय निरंतर पदानुक्रम, यूपी की जाति संरचना की विशेषता है। उत्तर प्रदेश में जाति और सामुदायिक राजनीति की वृद्धि और मुखरता आर्थिक विकास को पर्याप्त और समान रूप से बढ़ावा देने में विफलता और शासन और नीति प्रक्रियाओं के केंद्रीकृत ढांचे की कमजोरी का परिणाम थी, जिसमें अधिकांश वर्गों, जातियों, समुदायों और समूहों को बाहर रखा गया था। राजनीतिक शक्ति और शासन उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को तीन सामाजिक ब्लॉकों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहले, उच्च जाति के हिंदू हैं, मुख्य रूप से ब्राह्मण, राजपूत और बनिया, जिनकी आबादी लगभग 20 प्रतिशत है और राज्य में सरकारी नौकरियों और जमींदारों पर हावी हैं (हसन 1998, कुमार, 2018) दूसरा ब्लॉक, लगभग 20 प्रतिशत, हिंदू मध्य जातियों का गठन करता है, जिसमें जाट, विशेष रूप से इस समूह के उच्च वर्ग, जैसे गुर्जर, यादव और कुर्मी शामिल हैं, जिन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) (भारत सरकार) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 1980) शेष आबादी में मुख्य रूप से मुस्लिम (17 प्रतिशत), अनुसूचित जाति (एससी) (21 प्रतिशत), और सबसे पिछड़ा वर्ग (एमबीसी) शामिल हैं, जिनकी आबादी में हिस्सेदारी भी लगभग 20ः (यूपी सरकार 2001) है। कुछ मुस्लिम और अनुसूचित जाति अमीर हैं और उन्हें मध्यम वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, लेकिन उनमें से अधिकांश गरीब हैं और अनौपचारिक क्षेत्र की नौकरियों में केंद्रित हैं, जो बेहद शोषणकारी और असुरक्षित परिस्थितियों में काम कर रहे हैं।

उत्तर प्रदेश में ग्रामीण वर्ग संरचना बहुत असमान है, जो बड़े जमींदारों के एक वर्ग और बड़ी संख्या में गरीबों की उपस्थिति से प्रतिष्ठित है। समान रूप से महत्वपूर्ण इसका अपेक्षाकृत छोटा मध्यम वर्ग है जिसे शिक्षा, सरकार, रोजगार और राजनीति तक विशेषाधिकार प्राप्त और प्रतिबंधित पहुंच के माध्यम से बनाया गया है। सबसे गरीब लोगों में अनुसूचित जाति, सबसे पिछड़ा वर्ग और धार्मिक अल्पसंख्यक शामिल हैं वंचित आबादी ने इस तथ्य के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की है कि विकास के लाभों को उच्च जातियों–वर्गों द्वारा उनके कुल बहिष्कार पर एकाधिकार कर दिया गया है। लोकतंत्र ने उन्हें राजनीतिक सत्ता के विशेषाधिकारों और विकास के अवसरों से उनके बहिष्कार के खिलाफ शिकायतों को हवा देने का अवसर प्रदान किया।

कई विद्वानों ने उत्तर प्रदेश के गांवों का गहन अध्ययन किया है, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण अध्ययन इस प्रकार हैं – अकादमिक अध्ययनों ने उत्तर प्रदेश राज्य और इसके ग्रामीण जीवन के विभिन्न पहलुओं का व्यापक रूप से दस्तावेजीकरण किया है।ॅ.ॅपेमत (1936) ने करीमपुर गांव में हिंदू जजमानी प्रणाली का अध्ययन किया। सुसान वाडली ने करीमपुर गांव का भी अध्ययन किया और शिकागो से अपना काम, शक्तिरू पावर इन द कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ करीमपुर धर्म (1975) प्रकाशित किया। अन्वेषण जारी रखने के लिए, ब्रूस डब्ल्यू डेर (1979) ने 1925–75 की अवधि के दौरान उसी गांव, करीमपुर में भोजन और गरीबी की बढ़ती बहुतायत का अध्ययन किया। बर्नार्ड एस कोहन (1987) ने माधोपुर (सेनापुर) के चमारों का अध्ययन किया। संयोग से, सेनापुर एक ठाकुर बहुल कृषि गांव है जो वाराणसी से 25 मील उत्तर में स्थित है। कोहन ने अपने अध्ययन में इस गांव के चमारों के पारंपरिक और ऐतिहासिक अतीत जैसे विभिन्न अतीत के कामकाज की खोज की। रुद्र दत्त सिंह (1948) ने भी श्रम विभाजन को समझने के लिए उसी गाँव का अध्ययन किया। उन्होंने एक भारतीय गाँव की एकता और विस्तार पर चर्चा लाने में सी.एस. कून के साथ सहयोग किया।

जिन चार आर्थिक क्षेत्रों में राज्य को विभाजित किया गया है, उनका असमान विकास हुआ है। आजमगढ़ जिले और पूर्वी क्षेत्र के अन्य जिलों की सामाजिक–आर्थिक और भौतिक स्थितियों में कमोबेश समान भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों, आर्थिक गतिविधि पैटर्न, जनसंख्या घनत्व और कृषि स्थितियों में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। पूर्वी क्षेत्र जिसमें आजमगढ़ पड़ता है, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में मध्य प्रदेश और पश्चिम में बिहार से घिरा है। यह क्षेत्र गंगा, यमुना और घाघरा नदियों और उनकी कई सहायक नदियों द्वारा पार किए गए महान गंगा के मैदान का पूर्वी भाग है। पथ आमतौर पर दक्षिण पूर्व में ढलान करता है। उत्तरी तराई बेल्ट को छोड़कर, जहां वार्षिक वर्षा 80–120 सेमी है, इस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु है, जिसमें औसत वार्षिक वर्षा 80–120 सेमी है। क्षेत्र में उच्चतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस और 47 डिग्री सेल्सियस के बीच और न्यूनतम 4 डिग्री सेल्सियस और 7 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। इस क्षेत्र

की मिट्टी कृषि की दृष्टि से समृद्ध है और इस क्षेत्र में 17 प्रतिशत वन पाए जाते हैं। यद्यपि राज्य खनिज संसाधनों के मामले में बहुत समृद्ध नहीं है, पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में कुछ खनिज जमा होने के लिए जाना जाता है। पूर्वी क्षेत्र राज्य के तीन पिछड़े क्षेत्रों में से एक है।

आजमगढ़ जिले में कृषि संरचना और कृषि संबंधों को समझना

आजमगढ़ जिला – आजमगढ़, उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी जिलों में से एक है, जो कभी प्राचीन कोसल साम्राज्य का हिस्सा था। बुद्ध के समय में उत्तर भारत के चार शक्तिशाली राजतंत्रों में कोसल का प्रमुख स्थान था, जब इसकी समृद्धि अपने चरम पर पहुंच गई थी। आज़मगढ़ जिले में कुछ को छोड़कर, शायद ही बहुत अधिक पुरातन मूल्य का कोई अवशेष है। इस जिले की प्रत्येक तहसील में कुछ निर्जन स्थल हैं, जिनके लिए और तालाब देखे जा सकते हैं और वे अपने बिल्डरों के बारे में अस्पष्ट किंवदंतियाँ रखते हैं। जिले के प्रारंभिक इतिहास का पता केवल मौजूदा पुरावशेषों से ही लगाया जा सकता है।

परंपराओं के अनुसार जिले के पूर्व रहने वाले भर या राजभर, सोएरिस और चेरस थे। एक स्थानीय परंपरा के अनुसार, राम के समय में अयोध्या के राज्य में शामिल भर देश पर राजभरों और असुरों का कब्जा था। जिले के फूलपुर तहसील के माहुल परगना के दिहादुआर में असिलदेव नाम का एक राजभर मुखिया रहता था; और उस स्थान के पुराने तालाब और टीले उसकी शक्ति के चिन्ह कहे गए हैं। एक अन्य परंपरा के अनुसार, कुरु के सबसे बड़े पुत्र परीक्षितष (आरसी मजूमदार और पुसालकररू 1965), ने एक बार उस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, जिसे अब निजामाबाद कहा जाता है और अनवांक में पुराना कोट, जिसके पास उनके और मुहम्मदों (अंधेरे) के बीच एक लड़ाई लड़ी गई थी। ब्रोकमैन, 1911)। एक परंपरा इस विश्वास को भी कुछ समर्थन देती है कि जिले को अयोध्या के प्राचीन साम्राज्य में शामिल किया गया था (जनगणनारू 2011) मनु द्वारा स्थापित सूर्यवंशी राजवंश जिले का सबसे पुराना ज्ञात राजवंश है।

वर्तमान में, आजमगढ़ जिला उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में स्थित है। आजमगढ़ डिवीजन के तहत, और $25^{\circ}17$ और $26^{\circ}17$ उत्तरी अक्षांश और 82.04 और 83.52. पूर्वी देशांतर के समानांतर घाघरा नदी के दक्षिण में स्थित एक अनियमित आकार का पथ शामिल है। आजमगढ़ पूर्व में मऊ जिले से दक्षिण में गाजीपुर और जौनपुर जिले से और दक्षिण पश्चिम में जौनपुर जिले से पश्चिम में सुल्तानपुर जिले से, उत्तर पूर्व में और उत्तर में क्रमशः अंबेडकर नगर और गोरखपुर जिलों से घिरा है। 2011 की जनगणना के अनुसार जिले का क्षेत्रफल 4054.00 वर्ग किमी है। जिले का राज्य के जिलों में चौथा स्थान है। जिले की कुल जनसंख्या 4,613,913 है जिसमें 4,220,512 ग्रामीण और शेष 393,401 शहरी भागों में रहते हैं। जिले में 7 तहसील हैं; ये तहसीलें आजमगढ़, सागरी, बुरहानपुर, निजामाबाद, लालगंज और मेहनगर हैं। जिले में शहरी आबादी 8.53 प्रतिशत है। आजमगढ़ तहसील में शहरी जनसंख्या सर्वाधिक 26.9 प्रतिशत है। जिले में 4,101 राजस्व और 301 निर्जन गांव हैं। आजमगढ़ पूर्व मऊ, दक्षिण–पूर्व में गाजीपुर, दक्षिण–पश्चिम जौनपुर और उत्तर–पश्चिम में फैजाबाद और सुल्तानपुर से घिरा है। इसमें सात तहसीलें और 22 विकास खंड थे (भारत की जनगणना, 2011)। आजमगढ़ जिले के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है।

आजमगढ़ की भूमि कार्यकाल प्रणाली

आजमगढ़ राज्य के पिछड़े जिलों में से एक है। पिछड़ेपन के कारण जिले ने अपनी विभिन्न योजनाओं में सरकार का विशेष ध्यान आकर्षित किया। पंचवर्षीय योजनाओं के तहत सरकार ने क्षेत्र के संतुलित विकास को सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कई उपाय और रणनीतियां की हैं।

आजादी से पहले और बाद में राजनीतिक लामबंदी के क्षेत्र में आजमगढ़ जिला हमेशा सबसे आगे रहा है।

आजमगढ़ का कृषि इतिहास और भूमि जोत की व्यवस्था और वहां रहने वाले मुख्य कृषि वर्ग का विवरण केवल 1801 से दिया जा सकता है। 1596 से 1801 तक आजमगढ़ का कृषि इतिहास खाली है। किसी भी प्रकार का एक भी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है और 1801 में अधिवेशन के बाद अमिलस्वी और उनके अधिकारी अवध के लिए रवाना हो गए। जिले को लगभग एक अपशिष्ट के रूप में वर्णित किया गया है जो एक या दो साल के दौरान पूरी तरह से विनाश का दृश्य बन जाएगा। (पैरू 1986रू 47; आजमगढ़ गजेटियर 1811रू103)।

अमीन (1981) के अनुसार पूर्वी जिले एक ऐसे क्षेत्र के विपरीत हैं जिसमें ऐतिहासिक रूप से अत्यधिक गरीबी और कृषि भूमि पर भारी दबाव के साथ घनी आबादी का दुर्लभ संयोजन रहा है। जबकि इन जिलों में काफी आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन हुए हैं, पश्चिम में ऐसा परिवर्तन बहुत धीमा रहा है। इन जिलों में बहुत उपजाऊ मिट्टी पर्याप्त वर्षा और प्रचुर मात्रा में श्रम है। लेकिन भू–स्वामित्व पैटर्न विषम हो गया है, उच्च और मध्यम जातियों के पास बड़े भूखंड हैं और निचली जातियाँ / वर्ग सीमांत या बौने भूखंड हैं। ब्रिटिश काल में कुछ जिलों में गन्ने की खेती की जाती थी और मिलों की स्थापना की जाती थी। यह जमींदार और बिचौलिए ही थे जिन्होंने गन्ने की खेती से लाभ उठाया और इसे किसानों के लिए एक अधिशेष संचयक के बजाय एक कर्ज चुकाने वाली फसल बना दिया।

भूमि और जाति व्यवस्था पारंपरिक भारत में परस्पर जुड़ी हुई है, आजमगढ़ में भूमि और जाति संबंधों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। समकालीन ग्रामीण भारत में पारंपरिक पदानुक्रमित व्यवस्था न तो जाति व्यवस्था का सार है और न ही इसके अपरिहार्य परिणाम बल्कि राजनीतिक शक्ति या राजनीतिक आर्थिक शक्ति की अभिव्यक्ति है। आजादी से पहले, आजमगढ़ जिले में भू–अधिकार की व्यवस्था जमींदारी थी, जिसने जमींदारों को भूमि–स्वामित्व में न्यायिक अधिकार दिए थे। जमींदार जो ज्यादातर ऊंची जातियों से थे, अकेले जमीन के मालिक थे और अन्य सभी उनके किरायेदार थे जो उनसे खेती करने और उन्हें जमीन का किराया देने का अधिकार रखते थे। आज़मगढ़ जिले पर 61वीं बंदोबस्त रिपोर्ट के अनुसार, देशी प्रथा ने जिलों में किसानों के दो महान आदेश बनाए थेरू (प) वे जो अधिक नौकरशाही कार्यों को करने के लिए खेत सेवकों को नियुक्त करते थे और (पप) वे जो अपने लिए सब कुछ करते थे। . पूर्व आदेश में ज्यादातर उच्च जाति के लोग थे, जबकि हिंदू और मुहम्मद की सभी निम्न जातियों को दूसरे क्रम में शामिल किया गया था।

उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि आजमगढ़ जिले में 2000–01 के तहत अनुसूचित जाति में सीमांत वर्ग की जोत की संख्या 11678 (96.16:) थी जो 2010–11 में घटकर 126905 (96.96:) हो गई। जो कुल अवलोकन के माध्यम से सभी आकार वर्ग में सबसे अधिक प्रभावित है, 2000–01 में 0.5 से नीचे के सीमांत आकार वर्ग के तहत भूमि जोत का आकार 83.47: था जो 2010–11 में बढ़कर 83.91: हो गया। 2000–01 में छोटे आकार की वर्ग भूमि जोत 3577 (2.90:) थी, जो 2010–11 में घटकर 3479 (2.66:) हो गई। अगर हम अर्ध मध्यम, मध्यम और बड़े आकार में भूमि जोत के आकार के बारे में बात करते हैं तो अधिक पितृत्व की जांच नहीं की जाती है। जबकि 2000–01 से बड़े आकार वर्ग की भूमि जोत का प्रतिशत अपरिवर्तित रहा है। वर्तमान आंकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट है कि सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए विभिन्न प्रयास और पिछले 10 वर्षों में भूमि सुधार (भूमि वितरण) जैसे कार्यक्रमों के बावजूद; लेकिन भूमि जोत में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं हुआ है। इस तथ्य के कारण कि वर्तमान में अधिकांश अनुसूचित जातियाँ खेतिहर मजदूर के रूप में काम कर रही हैं।

भूमि सुधारों का कार्यान्वयन और इसका प्रभाव राज्य के सभी क्षेत्रों में भिन्न होता है। जिस तरह से इन सुधारों को डिजाइन और कार्यान्वित किया गया था, वह संचयी असमानता से बिखरी हुई असमानता में बदलाव लाया और जाति और भू–स्वामित्व के बीच संबंध पूरी तरह से कभी नहीं टूटा, क्योंकि ऊंची जाति के जमींदार सबसे बड़े भूमि मालिक, काश्तकार बने रहे जिन्होंने जमीन खरीदी या जमीन से लाभ उठाया। सुधार ज्यादातर ओबीसी थे और दलित वर्ग कार्यात्मक रूप से भूमिहीन कृषि श्रमिक बना रहा (त्रिवेदी, 2014)।

भूमि पर बिचौलियों के अधिकारों को समाप्त करने और भूमि जोतने वालों को मालिकाना अधिकार देने के लिए 1952 में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम पारित किया गया था। कई अन्य काश्तकारी सुधार जैसे कृषि जोत की सीमा, खंडित भूमि का समेकन और भूमिहीनों को भूमि का वितरण कृषि प्रणाली के भीतर शोषण और सामाजिक अन्याय के सभी तत्वों को समाप्त करने के लिए अपनाया गया ताकि सभी वर्गों को स्थिति और अवसर की समानता सुनिश्चित की जा सके। ग्रामीण आबादी का। भूमि सुधार जो कृषि संरचना में आमूल–चूल परिवर्तन ला सकते थे और वितरणात्मक न्याय के एक उपाय की शुरुआत कर सकते थे, कृषि संरचना में आवश्यक परिवर्तन लाने में विफल रहे (सिंह, 1987, पृष्ठ 125)। उच्च जातियों और मध्यम किसान जातियों के बड़े किसान अभी भी अधिकांश कृषि भूमि के मालिक हैं। भूमि का बड़ा हिस्सा अभी भी पारंपरिक उच्च जातियों के पास है। अन्य मध्यम और निम्न मध्य जातियों के पास सीमांत भूमि है। अनुसूचित जातियों के बीच भूमि वितरण के लिए भूमि सुधार कानूनों को लागू करने से शायद ही कोई ठोस परिणाम प्राप्त हो सके। भूमिहीनता अभी भी अनुसूचित जातियों में तीव्र रूप में व्याप्त है।

आजमगढ़ जिले में तकनीकों और प्रथाओं के साथ–साथ कृषि उत्पादकता प्रति कृषि उत्पादन के मूल्य के संदर्भ में मापी गई है, जो कमोबेश राज्य के औसत के समान है। आजमगढ़ और क्षेत्र के अन्य जिलों में भूमि का वितरण बहुत ही विषम है, जिसके परिणामस्वरूप निचले स्तर पर परिवारों की एक बहुत बड़ी संख्या में औसत आय की तुलना में बहुत कम आय होती है। आजमगढ़ जिले में कृषि उत्पादन संतोषजनक नहीं है। जिलों में खाद्यान्न का उत्पादन कभी भी इसकी आवश्यकता से अधिक नहीं रहा है। आजमगढ़ में जोत का आकार बहुत छोटा और आर्थिक नहीं है। इन गैर–आर्थिक भूमि जोतों ने जिले में कृषि उत्पादन पर काफी हद तक प्रतिकूल प्रभाव डाला है। इन सभी कमियों और सीमाओं के बावजूद कृषि उत्पादन के नए उपकरणों के माध्यम से कृषि उपयोग के लिए शुद्ध क्षेत्र को बढ़ाने और रासायनिक उर्वरकों के उपयोग और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के साथ भूमि को अधिक उपजाऊ बनाने के प्रयास किए गए

आजमगढ़ में जाति व्यवस्था

भू–स्वामित्व और जाति पदानुक्रम के बीच घनिष्ठ अंतर्संबंध था। कृषि संरचना को भूमि के स्वामित्व में बड़ी असमानता द्वारा चिह्नित किया गया था। जमी हुई जातियों के जमींदारों की एक छोटी संख्या के पास गाँव की अधिकांश भूमि का स्वामित्व था, जबकि बड़ी संख्या में छोटे किसानों को अपने अस्तित्व के लिए छोटे–छोटे खंडित जोतों पर निर्भर रहना पड़ता था। और सबसे नीचे, भूमिहीन खेतिहर मजदूरों का एक विशाल बहुमत मौजूद था, जिनकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति और भी बदतर और दयनीय थी। जमींदार निरपवाद रूप से मध्यवर्ती कृषक जातियों के थे और खेतिहर मजदूर अनुसूचित जातियों और अन्य निचली जातियों के थे, जिसके कारण सामाजिक अक्षमताओं के कारण आर्थिक अक्षमताएं बढ़ गईं

1901 की जनगणना के अनुसार, आजमगढ़ मुख्य रूप से एक हिंदू जिला (85.85:) था जिसमें कम से कम 76 विभिन्न जातियाँ थीं। प्रमुखों का विवरण नीचे दिया गया है (गज़ेटियर, 1989, पृष्ठ 103)। औपनिवेशिक काल के दौरान चमार सबसे बड़ा एकल वर्ग था और सामूहिक रूप से बड़ी मात्रा में भूमि रखता था। लेकिन उनकी व्यक्तिगत जोत छोटी थी और उनमें से ज्यादातर भूमिहीन मजदूर थे जो सामाजिक पदानुक्रम में सबसे निचले स्थान पर थे। अहीर (यादव) कृषक जातियों की रीढ़ थे। आजमगढ़ के ब्राह्मणों को मुख्य रूप से ष्सरजूपारीष् के रूप में वर्णित किया गया था और वे कोई उच्च धार्मिक पद नहीं रखते थे। उनकी जमीन जायदाद छोटी थी, गोपालपुर परगना में अखाइचंद के मिश्रा जैसे बड़े समुदायों के लिए उम्मीद थी।

जमींदार जातियों में अब तक राजपूत (ठाकुर) महत्वपूर्ण थे। कुछ परगना में उनकी जोत का अनुपात 89.14 से 17.04 प्रतिशत (पै, 1986, पृष्ठ 49) के बीच था।

पूर्वी उत्तर प्रदेश की जाति संरचना कठोर और विशिष्टतावादी नहीं है, जैसा कि भारत के दक्षिणी भागों में इसके समकक्ष थे। पूर्वी यू.पी. मुख्य रूप से एक कृषि है जिसमें जाति लोगों के धार्मिक और सामाजिक अनुभव के केंद्र में है। निरंतर पदानुक्रम श्बल्कि तेज विभाजन और अंतर, इन क्षेत्रों की जाति संरचना की विशेषता है। ऐतिहासिक रूप से, ब्राह्मणवादी जाति पदानुक्रम लगभग चार स्तरीय वर्ण व्यवस्था इस क्षेत्र में पूरी तरह से स्पष्ट है। चार उच्च जातियाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और कायस्थ हैं। 1931 की जनगणना के अनुसार, ब्राह्मणों की संख्या यूपी में 9: से अधिक थी। ब्राह्मणों की कुल संख्या का 40: प्रतिनिधित्व करते हैं (हसन, 1998, पृ.9)। इस प्रकार की विभेदित जाति विन्यास जिसमें उच्च जातियों का व्यापक भौगोलिक विस्तार है, ने यू.पी. में जाति वर्ग का एक विशिष्ट पैटर्न स्थापित किया। मुसलमानों में भी जाति व्यवस्था प्रचलित थी, शेख, पठान, सैय्यद, अशरफ, अंसारी और जुलाहा महत्वपूर्ण मुस्लिम जातियाँ थीं। विभिन्न प्रकार की जातियों और उप–जातियों (मुस्लिम और साथ ही हिंदू) के बीच सख्ती से देखे गए भेदों के अलावा, इस क्षेत्र में बुनियादी सामाजिक विभाजन, जिसे कम से कम स्थानीय रूप से प्रभावशाली तत्वों द्वारा माना जाता था, वह था शरीफ़ (या अशरफ, यानी सम्मानित वर्ग) और रज़ील (या मेहनतकश लोग)।

आजमगढ़ जिले में लगभग 84प्रतिशत आबादी हिंदू थी, जबकि राज्य की औसत 79.73 प्रतिशत थी। मुसलमान 16 प्रतिशत थे और शेष 0.42 प्रतिशत में सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन और अन्य शामिल थे (जनगणना, 2011) सबसे अधिक हिंदू जातियाँ हैंरू ब्राह्मण, राजपूत या छत्रियाँ, भर, कोइरी, भूमिहार, लूनिया (नोनिया) और बनिया, यादव (अहीर), कुर्मी, खरास, लोहार, कुम्हार, तेली, नाइस, कलवार,

केवट, पाल (गडेरिया)), सोनार, खटीक चमार, पासी, धोबी, धरकर, मुशर्र, मल्लाह आदि। ब्राह्मणों में से अधिक संख्या में सरवरिन या सरजुपारी हैं। राजपूत, जो क्षत्रिय होने का दावा करते हैं, उनकी कुल संख्या और उनकी सामाजिक स्थिति के मामले में सबसे आगे हैं। वे विभिन्न प्रकार के कुलों, सोमबंसिस, चंदेल, निकुंभ, चौहान, राठौर, रघुबंसिस, सीकरवार और लूनिया (नोनिया) से संबंधित हैं। बनिया कंडु हैं, एक ऐसी जाति जो भारभुज के साथ आत्मीयता रखती है। बनिया सागरी में असंख्य हैं लेकिन सभी तहसीलों में पाए जाते हैं। व्यक्तिगत सेवा, सामान्य श्रम और कुछ हद तक खेती में लगे कहार सभी तहसीलों में पाए जाते हैं। अहीर और कुर्मी दोनों ही स्वच्छ खेती करने वाली जाति हैं; दोनों लगभग थीसिस में पाए जाते हैं। पासी, धोबी और मुशर जैसी अन्य जातियों की तुलना में सभी तहसीलों में चमारों की आबादी सबसे अधिक है। चमार जिनका पारंपरिक व्यवसाय खाल और खाल के साथ काम करने से संबंधित था, अभी भी पूरे उत्तरी भारत में मृत जानवरों को हटाने के लिए जिम्मेदार हैं और मादा चमार दाइयों के रूप में कार्य करती हैं (कोहन, 1987)। जिले के अधिकांश मुसलमान सुन्नी संप्रदाय के हैं। मुसलमान जुलाहा (बुनकर), शेख, सैय्यद, अशरफ, अंसारी और पठान में बंट गए। उन्होंने सरायमीर, मुबारकपुर के कस्बों में बहुमत और फूलपुर, चिराकोट, आजमगढ़ और कई अन्य स्थानों में एक पर्याप्त अल्पसंख्यक का गठन किया।

कुल जनसंख्या अनुसूचित जाति की है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या में 26.62 प्रतिशत और शहरी जनसंख्या में 12.18 प्रतिशत है। अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत लालगंज तहसील (33.56) में दर्ज है जबकि सबसे कम बुरहानपुर तहसील (22.63) में पाया जाता है। इस जिले की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है। ग्रामीण इलाकों में रहने वाली अधिकांश अनुसूचित जातियां खेतिहर मजदूर हैं। यूपी। पूरे भारत में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या (20.प्रतिशत) का उच्च प्रतिशत है, तो शेष भारत (16.6) प्रतिशत है। ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी जनसंख्या (23 प्रतिशत) शहरी क्षेत्रों (12.7 प्रतिशत) से लगभग दोगुनी है। 2011 की जनगणना (जनगणना, 2011) में 66 प्रकार की अनुसूचित जातियाँ सूचीबद्ध हैं।

जनगणना 2011 के अनुसार जिले में कुल जनसंख्या 1372032 कार्य गतिविधियों में लगी हुई थी0 57.2 प्रतिशत श्रमिक अपने कार्यों को मुख्य कार्य (रोजगार या 6 महीने से अधिक कमाई) के रूप में वर्णित करते हैं, जबकि 42.8 प्रतिशत आजीविका प्रदान करने वाली सीमांत गतिविधि में शामिल थे या 1372032 के 6 महीने से कम थे। 311060 मुख्य कार्य में लगे श्रमिक कृषक (मालिक या सह–स्वामी) थे जबकि 153665 कृषि मजदूर थे।

इस जिले में कार्य भागीदारी दर जिले की कुल जनसंख्या 4,613,913 है, जिसमें 29.74 प्रतिशत श्रमिक तथा शेष 70.26 प्रतिशत गैर–श्रमिक हैं। श्रमिकों में 17 प्रतिशत मुख्य श्रमिक हैं और शेष 12.94 प्रतिशत कुल जनसंख्या के सीमांत श्रमिक हैं। मुख्य कार्यकर्ताओं की संख्या आजमगढ़ तहसील में सर्वाधिक 19.17 प्रतिशत तथा फूलपुर तहसील में न्यूनतम 15.69 प्रतिशत है। सीमांत श्रमिकों के मामले में बुरहानपुर तहसील में सर्वाधिक प्रतिशत 14.28 प्रतिशत है जबकि निजामाबाद में सबसे कम प्रतिशत 11.25 प्रतिशत है। जिले में श्रमिकों में 31.02 प्रतिशत कृषक तथा 27.58 प्रतिशत अन्य श्रमिक हैं।

उपरोक्त तालिका इस तथ्य का द्योतक है कि इस जिले में बेरोजगारी और अल्प रोजगार की समस्या व्यापक रूप से विकट है। इस जिले से बड़ी संख्या में लोगों को मौसमी या नियमित रोजगार की तलाश में देश के अन्य हिस्सों में पलायन करना पड़ता है। मलेशिया, बर्मा, सिंगापुर, बर्मा और खाड़ी देशों (सऊदी अरब, ओमान, क्वाइट, आदि) जैसे अन्य देशों में प्रवास अतीत में आबादी के निचले तबके के बीच काफी आम था, लेकिन समकालीन परिदृश्य में इसकी जाँच की गई है आव्रजन पर प्रतिबंध।

निष्कर्ष

परंपरागत रूप से, अंतर–जाति संबंध बहुत कठोर थे। विभिन्न जातियों और उपजातियों के सदस्य लगभग पानी के तंग डिब्बों में रहते थे और अंतर्जातीय भोजन और विवाह या तो वर्जित थे या उन्हें तीखी नज़र से देखा जाता था। हाल के परिदृश्य में काफी बदलाव आया है, खासकर आजादी के बाद की अवधि में, खासकर 1980 के दशक के बाद। अंतर्जातीय भोजन को अब जिले में कहीं भी विशेष रूप से

कस्बों में लोगों द्वारा अस्वीकृति के रूप में नहीं देखा जाता है। अंतर्जातीय विवाह हालांकि बहुत आम नहीं हैं, अब पहले की तुलना में अधिक बार होते हैं और शिक्षा के प्रसार, पश्चिमीकरण के प्रभाव, बढ़ती लैंगिक समानता और बाद में लिंग को हटाने के परिणामस्वरूप जाति के आधार पर विवाह पर कई पारंपरिक प्रतिबंध धीरे–धीरे गायब हो रहे हैं– आधारित विकलांगता।

इस जिले में भूमि सुधार (यूपी जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1951, भूमि वितरण) और अन्य राज्य पहलों के प्रभाव ने वंचित जातियों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में कई महत्वपूर्ण बदलाव लाए। यह भी देखा गया है कि अनुपस्थित जमींदारीवाद काफी हद तक गायब हो गया है। हालांकि, विकल्प के रूप में उद्योग की कमी के साथ कृषि अभी भी पिछड़ी हुई है रोज़गार ग्रामीण अभिजात वर्ग (उच्च जातियाँ), जिनमें मुख्य रूप से जमींदार शामिल हैं, जो कई सदियों से भूमि जोतने वाले का शोषण करते रहे हैं, को यादव और कुर्मी जैसी मध्यम जाति श्रेणियों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, जो प्रगतिशील किसान हैं जो भूमि के मालिक हैं और पूरी ताकत से खेती करते हैं। कृषि की आधुनिक तकनीक के साथ–साथ।

इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि 1980 के दशक से, चावल के भ्ल्टे के प्रसार, जोतों का समेकन, नलकूपों की शुरूआत, ग्रामीण बिजली ने कृषि में काफी परिवर्तन किया है। शहरीकरण का महत्वपूर्ण पहलू हुआ है, जिससे कमजोर वर्गों (दलितों और एमबीसी) के लिए कृषि फार्मों, ईंट भट्टों, निर्माण स्थलों और शहरों में रिक्शा खींचने पर रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है। त्रिपाठी (2012) के अनुसार, इस क्षेत्र में पोस्टमंडल चरण ने मध्यम जाति के अधिक ध्रुवीकरण को दर्शाया है। भूमि का स्वामित्व भी बदल गया है और भूमि मध्यम जाति, विशेषकर यादवों में स्थानांतरित हो गई है। समापन टिप्पणी के रूप में, अवलोकन के दौरान यह पता चलता है कि जमींदारों और पुराने संरक्षक संबंधों पर पूर्ण निर्भरता गायब हो गई है और दलितों ने गैर–अर्थ व्यवसायों को छोड़ दिया है और सामाजिक गरिमा के पतन से बचा है। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड (9 नवंबर 2000) के अलग होने के बाद केवल चार आर्थिक क्षेत्रों तक ही सीमित था, ये पश्चिमी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र और बुंदेलखंड हैं।

वह मुगलों के अधीन अधीनस्थ सैन्य अधिकारी थे। अप चाकला एक अनुमंडल था। अपप अमिल ने अवध के नवाबों के तहत आधिकारिक रूप से राजस्व एकत्र किया। अपड्डप इन सामाजिक समूहों (अखिल भारतीय रिपोर्ट कृषि जनगणना 2010–11) के कल्याण के लिए नीतिगत निर्णय की सुविधा के लिए कृषि जनगणना 1980–81 के दौरान पहली बार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की कृषि परिचालन जोत की जानकारी अलग–अलग एकत्र की गई थी।

संदर्भ

1. अम्बेडकर, बी.आर. (1945) कास्ट इन इंडियारू देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, दिल्ली सिद्धार्थ, बुक्स।
2. चौहान, बीआर (2009) रूरल लाइफरू ग्रास रूट्स पर्सपेक्टिव्स, नई दिल्लीरू कॉन्सेप्ट पब्लिशिंग कंपनी भारत की जनगणना, (2011)। भाग जिला जनगणना पुस्तिका आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ की ग्राम एवं नगर निर्देशिका।.
3. कोहन, बर्नार्ड एस. (1987)। इतिहासकारों और अन्य निबंधों के बीच एक मानवविज्ञानी में द पास्ट्स ऑफ ए इंडियन विलेज, नई दिल्ली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
4. सी पार्वथम्मा। (1981)। समाज के कमजोर वर्ग– भारत में अनुसूचित जाति, सामाजिक बुलेटिन, 30 (1), 54–72
5. दत्त और रैवेलियन (2002)। ष्क्या भारत की आर्थिक वृद्धि गरीबों को पीछे छोड़ रही है? जर्नल ऑफ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव्स, 16(3), 89–108।
6. जिला गजेटियर, आजमगढ़ (1989)। वॉल्यूम। ग्ग्ग्प्ट, बलवंत सिंह द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार, जिला गजट विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
7. द्रेज और सेन, (1995)। भारतीय विकासरू क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य, दिल्ली, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। यूपी सरकार (2001)रू सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट (हुकुम सिंहरू अध्यक्ष), सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, लखनऊ।
8. हैग वॉल्सली (1958)। कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वॉल्यूम।दिल्ली पीपी.158

9. हसन, जोया। (1998)। क्वेस्ट फॉर पावर उत्तर प्रदेश, दिल्ली में विपक्षी आंदोलन और कांग्रेस के बाद की राजनीति, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, पी–9
10. कुमार, सत्येंद्र (2018)। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि परिवर्तन और नई सामाजिकता, आर्थिक राजनीतिक साप्ताहिक, स्प्प् (26 और 27), 39–47
11. मजूमदार, आर.सी. और पुसालकर, ए (1965)। भारतीय लोगों का इतिहास और संस्कृति, वॉल्यूम। मैं वैदिक युग, बॉम्बे
12. नूरबख्श एफ, 2003, भारत में मानव विकास और क्षेत्रीय असमानता, बिजनेस स्कूल अर्थशास्त्र, ग्लासगो विश्वविद्यालय, चर्चा पत्र संख्या 2003–12। ीजजचरू/ /ूहसं.ब.ना/उमकपं–22245–मद।
13. पाई, सुधा. (1986)। यूपी में बदलते कृषि संबंधरू उत्तर–पूर्वी क्षेत्रों का एक अध्ययन नई दिल्लीरू इंटर–इंडिया प्रकाशन।
14. (2000)। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों के सामाजिक–आर्थिक और राजनीतिक प्रोफाइल को बदलना, जर्नल ऑफ इंडियन स्कूल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, 12 (3 और 4), 405–422।
15. (2004)। सोशल कैपिटल, पंचायत और ग्रासरूट डेमोक्रेसीरू द पॉलिटिक्स ऑफ दलित एसेरशन इन टू डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश इन द्वालपायन भट्टाचार्य (सं.) इंट्रोगेटिंग सोशल कैपिटलरू द इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्लीरू सेज पब्लिकेशंस।
16. रहेजा, जी.जी. (1988)। पॉइज़न इन द गिफ्टरू रिचुअल प्रेजेंटेशन एंड द डोमिनेशन कास्ट इन ए नॉर्थ इंडियन विलेज, शिकागोरू शिकागो यूनिवर्सिटी प्रेस।
17. रूडोल्फ एल.आई. एंड एस. एच. रूडोल्फ, (1987)। परंपरा की आधुनिकतारू भारत में राजनीतिक विकास, नई दिल्ली, ओरिएंट लॉन्गमैन। सिंह बलवंत (1989)। आजमगढ़रू जिला गजेटियर, वॉल्यूम। ग्ग्ग्प्ट। उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ। सिंह, आर.पी. (1987) सोशियोलॉजी ऑफ रूरल डेवलपमेंट। दिल्लीरू डिस्कवरी पब्लिशिंग हाउस।
18. सिंह, रुद्र दत्त, (1948)। एक भारतीय गांव में श्रम का विभाजनश, सी.एस. कून (सं.) में। पाठकरू सामान्य नृविज्ञान।
19. सिंह, योगेंद्र. (2002)। चानूखेड़ारू वंदना मदन में पूर्वी उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक परिवर्तन (सं.). द विलेज इन इंडिया, नई दिल्लीरू ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
20. सांख्यिकीय डायरी उत्तर प्रदेश, 2015, अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी प्रभाग राज्य योजना संस्थान योजना विभाग, उत्तर प्रदेश।
21. थोराट, सुखदेव और जोएल ली। (2005) जाति भेदभाव और खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम, आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, एक्स्ट्रा लार्ज (39), 4198–4201
22. त्रिवेदी, पी.के. (2014) एके सिंह और संतोष मेहरोत्रा में भूमि सुधार और दलित (सं।) इक्विटी और विकास के लिए भूमि नीतियां, नई दिल्लीरू ऋषि प्रकाशन।
23. त्रिपाठी, तूलिका (2012) उत्तर प्रदेश की सफाई कर्मचारी योजनारू जाति प्रभुत्व जारी है, आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, 47 (37), 26–29
24. वाडली, एस.एस. (1975) शक्तिरू करीमपुर धर्म की अवधारणात्मक संरचना में शक्ति, शिकागो शिकागो विश्वविद्यालय प्रेस।
25. वाइज़र, डब्ल्यू.एच. (1958)। द हिंदू जजमानी सिस्टम, लखनऊ पब्लिशिंग हाउस
26. मजूमदार, आर.सी. और पुसालकर, ए (1965) भारतीय लोगों का इतिहास और संस्कृति, खंड वैदिक युग, बॉम्बे, पीपी.299
27. आजमगढ़ गजेटियर, वॉल्यूम। आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत डी.एल. डार्क–ब्रॉकमैन, इलाहाबाद (1911) पीपी 155।
28. अबुल फजल द्वारा लिखित आइने–ए–अकबरी। यह सम्राट या अकबर के साम्राज्य (मजूमदार, 2007) के प्रशासन को रिकॉर्ड करने का 16वीं शताब्दी का विस्तृत दस्तावेज है।